INDUSTRIAL POLICY AND LICENSING SYSTEM IN INDIA:

औद्योगिक नीति से आशय सरकार के उस विचार से है जिसके अन्तर्गत वह उद्योगों के विकास के ढाँचे को निर्धारित करती है जिसके कुछ नियम और सिद्धान्त होते हैं। इस नीति के निर्धारण में देश की आर्थिक संरचना, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक व्यवस्था और निवेशकों की सलाह का ध्यान रखा जाता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त 6 अप्रैल, 1948 को भारत सरकार ने अपनी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे:

(i) सभी लोगों को व्यय और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए सामाजिक ढाँचे की स्थापना करना।

(ii) देश के प्रच्छन्न संसाधनों का समुचित विदोहन करना।

(iii) रोजगार के नवीन अवसरों का निर्माण करना।

(iv) कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों की उत्पादिता में वृद्धि करना।

Scanned with CamScanner

(v) निजी उद्यमों का नियमन करना।

(vi) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का विभाजन करना।

Chief Characteristics of Industrial Policy of 1948 :→

1 उद्योगों का वर्गीकरण :— स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योगों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया :—

(क) राज्य एकाधिकारी उद्योग :→ इस क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले उद्योगों में प्रतिरक्षा के सामान का निर्माण करने वाले उद्योग, अणु शक्ति का निर्माण और नियंत्रण करने वाले उद्योग, रेल यातायात आदि प्रमुख हैं। इन उद्योगों के निर्माण में सरकार का एकाधिकार होता है।

(ख) आधारभूत उद्योग :→ इसके अन्तर्गत कोयला, लौह व इस्पात, जहाज-निर्माण, वायुयान निर्माण, टेलीफोन तार, बेतार के तार, खनिज तेल आदि उद्योगों को सम्मिलित किया गया है।

(ग) नियमित उद्योग :→ इस श्रेणी में 18 उद्योग सम्मिलित होंगे जिनमें मोटर

Scanned with CamScanner

कार, ट्रैक्टर, इन्जीनियरिंग का सामान, भारी मशीनें, विद्युत उपकरण, अन्न तथा सामुद्रीयातायात प्रमुख हैं।

(घ) निजी उद्योग :→ शेष उद्योगों को निजी निजी उद्योगों के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन सरकार प्रगतिशील ढंग से इस क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकेगी।

2. कुटीर एवं लघु उद्योग की भूमिका :→

औद्योगिक नीति, 1948 में स्पष्ट किया गया अर्थव्यवस्था के विकास में कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व पर बल दिया गया है।

3. विदेशी पूंजी की भूमिका :→ औद्योगिक नीति, 1948 में स्पष्ट किया गया कि विदेशी पूंजी के अन्तर्वाह को प्रोत्साहित किया जायेगा क्योंकि इसमें पूंजी की पर्याप्त पूर्ति और तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

4. औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के उपाय :→

अन्य बातों के अलावा इस नीति में सामाजिक न्याय, न्यायोचित मजदूरी, औद्योगिक मामलों में श्रमिकों का बढ़ता हुआ

Scanned with CamScanner

योगदान तथा आत्यधिक कर लगाकर आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने पर बल दिया गया।

5. केन्द्र में केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की स्थापना एवं उत्पादन क्षेत्र के विनियोग में वृद्धि के अनुरूप का नीति का प्रारूप निर्धारित किया गया।

क्रमशः

धन्यवाद